उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना

१२२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है और अब तक केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में कितनी सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : राम गंगा परियोजना पर सितम्बर, १९५९ के अन्त तक हुई प्रगति निम्नलिखित है :—

(क) कंक्रीट का पुल	कार्य का ६४.५ प्रतिशत भाग पूरा किया गया
(ख) छेदन कार्य (ड्रिलिंग)	कार्य का ६३.६ प्रतिशत भाग पूरा किया गया
(ग) औजारों की उपलब्धि	कार्य का ६१.७ प्रतिशत भाग पूरा किया गया

जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है १९५९–६० में विविध विकास योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण देने के लिये ४५४.७४ लाख रुपये की राशि नियत की गई है। ये योजनाएं साथ ही साथ राम गंगा परियोजना को भी सम्मिलित करती हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति शीघ्र ही दे दी जायेगी।

डाक तथा तारघर

१२२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के आयव्ययक में डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिये कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) प्रत्येक मद के लिये प्रत्येक परिमण्डल को कितनी-कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) यह राशि किन आधारों और सिद्धान्तों के अनुसार दी गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) १९५९–६० के बजट में डाकघर, तारघर, टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये नियत की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

(१) डाक घर खोलने के लिये	८ लाख
(२) तारघर खोलने के लिये	१६ लाख
(३) टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये	.३६ लाख
(४) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये	.३२ लाख

(ख) उक्त सूचना देने वाले विवरण पत्र सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८**]

(ग) नये डाक व तारघर, टेलीफोन केन्द्र व सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये सिद्धान्त लागू किये गए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इन विभिन्न दफ्तरों को खोलने की संभावना का अनुमान लगाकर परिमण्डलों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार राशियां नियत कर दी जाती हैं।

Licensing of Cobblers on Railways

1228. **Shri Ram Krishan Gupta:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether there is any proposal

to licence cobblers plying their trade in railway premises?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): With a view to prevent harassment to cobblers who for a long time have been attending to the needs of passengers in or near III Class waiting halls at certain stations, Railway Administrations have been instructed to issue licences in their favour to enable them to continue to ply their trade.

Re-Auctioning of Timber by Andaman Government Timber Depot

1229. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleasd to rfer to the reply given to Starred Question No. 173 on the 20th November, 1959 and state:

(a) whether Government have since received the detailed information about re-auctioning of 170 tons of timber by the Andaman Government Timber Depot;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps, if any, taken by Government in the matter?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): (a) to (c). The detailed information promised in reply to Starred Question No. 173 answered in the Lok Sabha on 20-11-59 was received only on 15-2-60. On examination, it was found that the information received was incomplete in many respects for the purposes of answering the assurance given on 20-11-59. A further enquiry has, therefore, been made on 4-3-60. In view of the fact that details of the transactions are in an office at Calcutta and correspondence has to be carried out between Delhi, the Andaman Islands and Calcutta, completion of the enquiry will take a little more time. The complete information will be placed on the Table of the Sabha as soon as the full facts of the case are received.

हिमाचल प्रदेश में भंवर घास

१२३०. { **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में जो भंवर घास लगाया जा रही है उसमें कहां तक सफलता मिलने की संभावना है; और

(ख) वर्ष १९५९-६० में अब तक इस पर कितना खर्च किया जा चुका है और इस से कितनी आय हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) नाहन और बिलासपुर वन विभागों में भावर घास के प्रवर्धन (propagation) से संतोषजनक परिणाम निकले हैं। यह ऊंचे स्थानों पर पैदा नहीं होती। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ दूसरे विभागों के उचित क्षेत्रों में इस का परीक्षण किया जायेगा।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर १९५९ तक १६,२६८ रुपये खर्च हुए हैं। १९५९-६० में भावर घास के एक्सट्रेक्शन (extraction) से लगभग २८,००० रुपये की रायल्टी (royalty) की आशा है।

Electric Locomotives

1231. Shri Subbiah Ambalam: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether requirements of electric locomotives upto the end of the Second Five Year Plan have been ascertained; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) A.C. locomotives 112 Nos. for through goods trains only on Eastern and South Eastern Railways. D.C. locomotives 22 Nos. for additional traffic on Central Railway.